

**राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना का कार्यान्वयन**

1456. श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना को कार्यान्वयित कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसे राज्यों को वाचित फिस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में तिलहनों के न मिलने के कारण 1987 में खरीफ की फसल में तिलहनों का उत्पादन काफी कम हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सरकार एक अधिनियम पारित करके एक ऐसी नीति अपनाने का विचार रखती है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों से बीज संकलित करने और फिर समस्त राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार इन्हें समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हाँ !

(ख) राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे "प्रजनक बीजों" के लिये अपने मांग पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को बिजाई से एक वर्ष पहले प्रस्तुत करें ताकि राज्य बीज निगम और राज्य विभागीय फार्मों द्वारा चलाये जाने वाले आधारों और प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये पूर्णित माला में प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जा सके। इससे राज्यों को राज्य स्तर पर

किसानों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।

(ग) 1987 के दौरान खरीफ तिलहन उत्पादन में बहुत से तिलहन उत्पादक राज्यों में व्याप्त सूखे को व्यापक स्थितियों के कारण कमी आने की सम्भावना है, बीजों की अनुपलब्धता के कारण नहीं।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्प्रिकलरों की खरीद के लिये कृषकों को अनुदान

1457. श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री 28 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में ताराकित प्रश्न 472 के दिए थे उत्तर को देखें और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में दृष्टिकों को स्प्रिकलरों की खरीद के लिए अलग अलग दरों पर अनुदान दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ये दरें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार दृष्टिकों को स्प्रिकलरों की खरीद करने के लिये एक समान दर पर अनुदान देने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) तक ही तक भारत सरकार का संबंध है, दो पृष्ठक योजनाएं चाले हैं, जिसमें अन्य बस्तुओं के साथ-साथ स्प्रिकल सेटी की खरीद करने के संबंध में भी किसानों के लिए राज सहायता की व्यवस्था शामिल है। इन योजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए एक समान दरें निर्धारित हैं।